9/26/24, 2:51 PM WhatsApp

Gaindakhali

आदेश

उप जिलाधिकारी, श्री पूर्णागिरि [illegible] के पत्र संख्या–923 / [illegible] / 2020–21 दिनांक [illegible] 2020 एवं पत्र संख्या–47 / रा०का०–भूमि आवंटन(लो०नि०–आवंटी) / 2020–21, दिनांक 23 [illegible] 2021 [illegible] हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी के पत्रांक–1474 / 12–1 दिनांक 23.12.2020 द्वारा प्रस्तुत आख्या व आधार पर Minutes of the High powered Committee of Uttarakhand State Disaster Management Authority (USDMA) meeting held on [illegible] के सन्दर्भ संख्या–180 / [illegible] PMU [illegible] 2020 [illegible] दिनांक 04 सितम्बर 2019 के अनुक्रम में, वर्ल्ड बैंक [illegible] प्रस्तुत परियोजना [illegible] नं० 01 एवं [illegible] को जोड़ने वाले पुल का निर्माण के सम्बन्ध में [illegible] संख्या–245 / सात–भू हस्ता० / 2020–21, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र संख्या–1570 / [illegible] दिनांक 31 दिसम्बर 2020 के अनुक्रम में, शासनादेश संख्या–111 / XXVII(7)50(39)-2013-2014 दिनांक 9 जुलाई, 2015 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, याचक विभाग की सहमति / अनापत्ति के आधार पर, शासनादेश संख्या–269 / [illegible] / 2002 दि० 15.02.2002 में निहित निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन ग्राम [illegible] नं०–1 के खाता नं०–11 [illegible] के खेत संख्या–80, रकबा 3.7060 है० मध्ये 0.004 है० एवं खाता संख्या–12, अन्य बंजर के खेत संख्या 43, रकबा 0.553 है० [illegible] है० कुल रकबा 0.007 है० तथा ग्राम [illegible] नं० 3 के खाता संख्या 64 [illegible] के खेत संख्या–01, रकबा [illegible] है० इस प्रकार कुल रकबा 0.009 है० भूमि ग्राम–[illegible] नं० 1 एवं [illegible] नं०–3 को जोड़ने वाले [illegible] पुल के निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत के नाम निःशुल्क नामान्तरण / हस्तान्तरण [illegible] प्रदान की जाती है:–

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिये भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और इसके लिए शासन [illegible] सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाये, तो उसके लिये [illegible] अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती [illegible] वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, [illegible] अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है, उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष बची रहती है तो मूल [illegible] को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन [illegible] हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 तथा U.P. Tenancy Act 1939 [illegible] काश्तकारी अधिनियम, 1939) की धारा–30 एवं इसके समकक्ष अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132 / 2011(एस०एल०पी०) (सी), संख्या–3109 / 2011 श्री [illegible] बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या–436 / 2011 / SLP(C) NO.20203 / 2007, झारखण्ड [illegible] बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक [illegible] जनवरी, 2011 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्त बिन्दु संख्या–01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

उप जिलाधिकारी, श्री पूर्णागिरि (टनकपुर), स्वीकृत भूमि को अधिशासी अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत के नाम निःशुल्क नामान्तरण एवं हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
जिलाधिकारी, चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

सं०प० – 2466 / VII-A.L.R.O. / सि०भू०नि०हस्ता० / World Bank, PWD टनकपुर / 2020–21, दिनांक 15 फरवरी, 2021

प्रतिलिपि, निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2– सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5– अपर जिलाधिकारी / भूलेख अधिकारी, चम्पावत।
6– उप जिलाधिकारी, श्री पूर्णागिरि (टनकपुर)।
7– अधिशासी अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।
8– तहसीलदार, श्री पूर्णागिरि (टनकपुर) मय पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, उक्त स्वीकृत भूमि [illegible] विभाग के नाम नियमानुसार भू–अभिलेखों में निःशुल्क नामान्तरण एवं हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी,
चम्पावत।

https://web.whatsapp.com 1/2